सिमडेगा जिला में कृषि भूमि–उपयोग के बदलते स्वरूप : एक भौगोलिक विश्लेषण

राँची विश्वविद्यालय, राँची

पीएच.डी. निबंधन हेतु शोध–प्रारूप

भूगोल विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय

2023

शोध निर्देशक

डॉ. राजेश कुमार लाल

असिस्टेंट प्रोफेसर

विश्वविद्यालय भूगोल विभाग

राँची विश्वविद्यालय, राँची

शोधार्थी

अरविन्द प्रसाद

एम0ए0, नेट

मो0 नं0–9771981751

Email ID- arvindprasadkonbegi@gmail.com

1. शोध शीर्षक का संक्षिप्त परिचय :–

सिमडेगा जिला झारखण्ड राज्य का 22वाँ जिला है, जिसका गठन 04 अप्रैल 2001 ई0 को हुआ तथा इससे पहले यह गुमला जिला का एक अनुमण्डल हुआ करता था। सिमडेगा जिला झारखण्ड राज्य के दक्षिण–पश्चिम दिशा में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार $20^0 10'$ से $20^0 40'$ उत्तर तथा देशान्तरीय विस्तार $84^0 0'$ से $84^0 34'$ पूर्व है। सिमडेगा जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 371731.70 हेक्टेयर है जिसमें 103726 हेक्टेयर भू–भाग कृषि भूमि के रूप में पहचाना गया है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 28 प्रतिशत भाग को सम्मिलित करता है तथा 100884.25 हेक्टेयर क्षेत्र वनाच्छादित है, यह लगभग कुल क्षेत्रफल का 27.15 प्रतिशत भू–भाग घेरता है। सिमडेगा जिला को निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया जा सकता है।

LOCATION MAP OF SIMDEGA DISTRICT, JHARKHAND

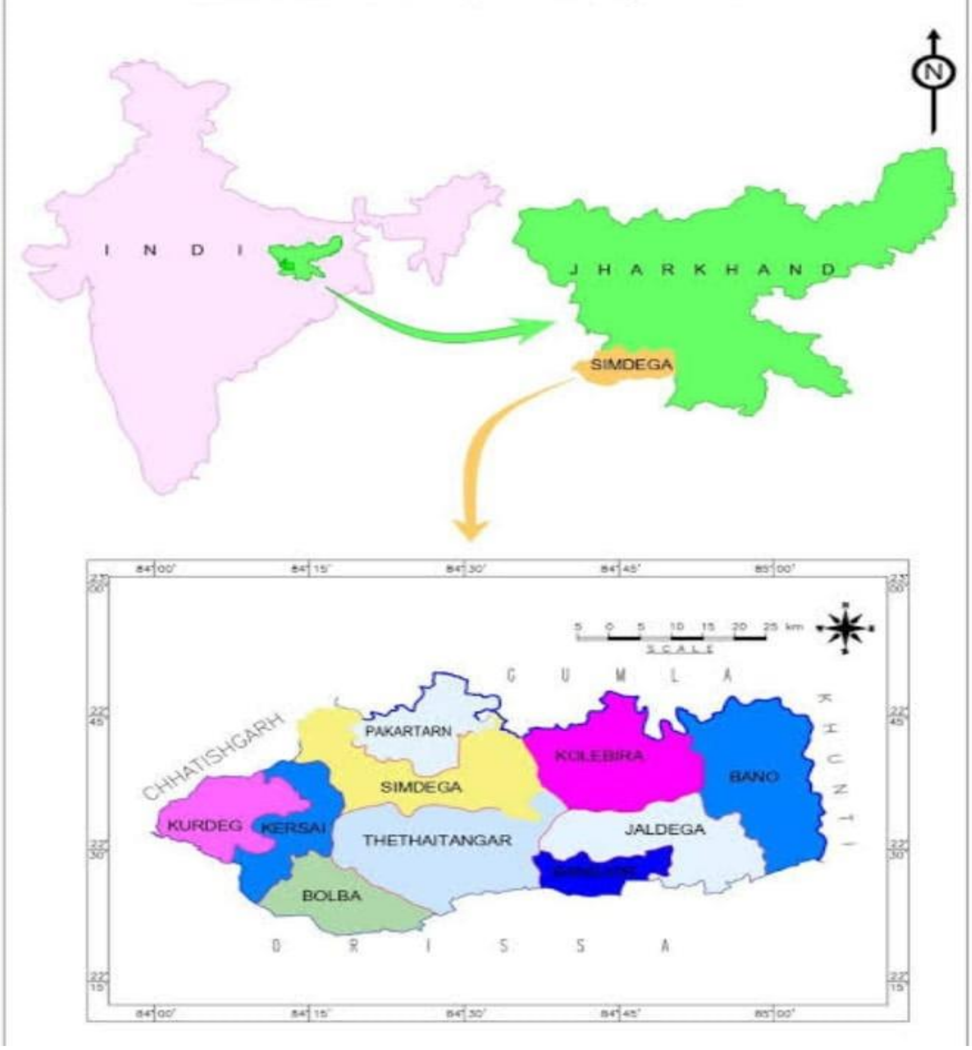

सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या 599813 है, जिसमें 299905 पुरूष तथा 299908 महिलाएँ हैं अर्थात् लिंगानुपात 1000 है, जो झारखण्ड का दुसरा सबसे ऊँचा लिंगानुपात वाला जिला है तथा जनसंख्या 160 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है जो झारखण्ड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है एवं जनसंख्या वृद्धि दर भी 16.62 प्रतिशत है। झारखण्ड (22.93 प्रतिशत) तथा भारत (17.64 प्रतिशत) से कम है, ये सभी कारक सिमडेगा जिला के सकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं। सिमडेगा जिला की ग्रामीण जनसंख्या 556880 (9284 प्रतिशत) तथा नगरीय जनसंख्या 42933 (7.16 प्रतिशत) है। साक्षरता दर 67.59 प्रतिशत है।

सिमडेगा में कुल 10 प्रखण्ड, 94 ग्राम पंचायत तथा 450 राजस्व ग्राम है। सिमडेगा जिला की प्रमुख नदियों में शंख तथा दक्षिण कोयल महत्त्वपूर्ण नदियों में है। इसके अलावे अन्य पहाड़ी नदियों में पालामाड़ा नदी, छिन्दा नहीं, गिरमा नदी, कुसमा नदी, सोनाजोर नदी, उतेल नदी, लुड़गी नदी, समरसिंधा नदी आदि प्रमुख है। इस जिला को रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा राँची तथा राउरकेला शहर से जोड़ा गया है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़ से भी सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है तथा सिमडेगा से होते हुए NH-143गुमला तथा राउरकेला को जोड़ती है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र सिमडेगा जिला पर तैयार किया है, अतः अध्ययन क्षेत्र के कुछ प्रखण्डों को प्रतिदर्श (SAMPLE) के रूप में पहले चयन किया जाएगा तथा चयनित गांवों के आधार पर शोध पत्र पूर्ण किया जाएगा।

2. अद्यतन स्थिति :–

भूगोल के क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग संबंधी अध्ययन विशिष्ट स्थान रखता है। कृषि भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप का अध्ययन भूगोल की एक शाखा कृषि भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है। वैसे तो कृषि कार्य नव–पाषाण युग से ही किया जा रहा है और उस समय कुछ सीमित फसलें ही उगायी जाती थी, परन्तु जैसे–जैसे समय में परिवर्तन होता गया, वैसे–वैसे कृषि भूमि उपयोग का स्वरूप भी बदलता गया। प्रारम्भ में जहाँ कृषि कार्य सीमित क्षेत्रों में हुआ करता था, इसके बाद कृषि क्षेत्र का विस्तार काफी बढ़ गया। परन्तु वर्तमान समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा

द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में तेजी से विस्तार होने से कृषि भूमि पुनः सीमित होने लगा है। फिर भी सभी क्रियाओं में आज भी कृषि का अपना अलग महत्व रखता है।

सभी प्राथमिक क्रियाओं में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की लगभग 58.2 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। जबकि कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र काफी सीमित है और इसी सीमित कृषि क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे अध्ययन का विषय भी ''सिमडेगा जिला में कृषि भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप का एक भौगोलिक अध्ययन'' है। सिमडेगा जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 371711.7 हेक्टयर है, जिसमें 100884.25 हेक्टेयर क्षेत्र वनाच्छदित है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 27 प्रतिशत क्षेत्र में फैला है। जबकि कृषि भूमि उपयोग के रूप में 103726 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग किया जाता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 28 प्रतिशत क्षेत्र में सीमित है, और इसी सीमित क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है, जहाँ आज जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला की जनसंख्या 599813 है, और यह बढ़ती आबादी ने सिमडेगा जिला को पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने में अक्षम बना रहा है।

पिछले दो से तीन दशकों में भौतिक पर्यावरण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से बदलाव हुए हैं और इस बदलावों से सिमडेगा जिला भी अछूता नहीं रहा है एवं इन बदलावों का प्रभाव कृषि–भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। अतः हमारे शोध का मुख्य विषय इस क्षेत्र में पिछले दो से तीन दशकों में कृषि भूमि उपयोग के स्वरूप में क्या बदलाव हुआ है, पर केन्द्रीकृत है।

इस प्रकार सिमडेगा जिला के कृषि भूमि उपयोग के स्वरूप में बदलाव आ रहे हैं, जिसको प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक जैसे जलवायु, मृदा, उच्चावय के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जैसे– सिमडेगा जिला में उष्ण कटिबन्ध प्रकार की जलवायु पायी जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 1300 मी0मी0 होता है, जो मुख्यतः जून से सितम्बर के मध्य प्राप्त होता है, वहीं ग्रीष्म ऋतु अत्यन्त तप्त लगभग 40^0C से 45^0C तक तापमान तथा शीत ऋतु अत्यन्त ठण्डा 10^0C से 2^0C तक तापमान पहुँच जाता है।

वहीं सिमडेगा जिला की मृदा मुख्यतः एन्टीसोल, इनसेप्टीसोल तथा अल्फीसोल प्रकार की पायी जाती है।

सिमडेगा की उच्च भूमि की मृदा प्राकृत रूप सें अम्लीय है तथा बालुआ प्रकार का है वहीं निम्न भूमि में मृदा के रूप में क्ले की प्रधानता है।

यदि सिमडेगा जिला की उच्चावच पर गौर किया जाए तो यह एक पर्वतीय, पठारी तथा निम्न भूमि वाला प्रदेश है। जहाँ कृषि भूमि के रूप में दोन तथा टाँड़ की प्रधानता है। इन उपलब्धता को निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता हैः–

1) उच्च भूमि – 62786.76 हेक्टेयर

2) मध्यम भूमि – 24148.75 हेक्टेयर

3) निम्न भूमि – 14489.25 हेक्टेयर

इस प्रकार सिमडेगा जिला की भौतिक पर्यावरणीय दशाओं में स्पष्ट होता है कि यहाँ फसल चक्रण पद्धति द्वारा अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन तथा विकास सम्भव है। परन्तु किसी भी क्षेत्र के कृषि विकास के लिये सिर्फ भौतिक कारकों का अनुकुल होना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके लिये वहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारक भी उतने भी उत्तरदायी होते हैं।

अतः सिमडेगा जिला की सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों पर गौर किया जाएगा तो सिमडेगा जिला एक आदिवासी बहुल पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। जहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है तथा 93 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है, एवं 66 प्रतिशत

परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या

कृषि तथा कृषि मजदूरी कार्यों में संलग्न है सिर्फ 29.06 प्रतिशत जनसंख्या ही गैर कृषि कार्यों में संलिप्त है।

इन आँकड़ों से पता चलता है कि सिमडेगा जिला के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 28 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सिमडेगा के कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का दबाव है एवं सिमडेगा जिला में किसी भी प्रकार का अन्य रोजगार प्रदत्त आर्थिक क्रियाकलापों का विकास नहीं हो पाया है। इससे मालूम चलता है कि सिमडेगा जिला में कृषि की कितनी महत्ता है, अतः इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिये कई प्रयास एवं अनेक योजनाएँ चलायी जा रही है जिनका प्रभाव कितना पड़ा है तथा किस तरह से कृषि भूमि उपयोग के स्वरूप में बदलाव आ रहे हैं इसका अध्ययन हमारे प्रस्तावित शोध से किया जाएगा।

फॉक्स (FAX 1956) के अनुसार :— निहित भूमि विशेषताओं के आधार पर किसी क्षेत्र के वास्तविक प्रयोजन के साथ उपयोग को भी भूमि उपयोग कहते हैं। भौगोलिक अध्ययन में भूमि प्रयोग, भूमि उपयोग तथा भूमि संसाधन उपयोग विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त होते हैं।

फॉक्स के अनुसार भूमि प्रयोग के अन्तर्गत कोई भू—भाग प्रकृति—प्रदत विशेषताओं के अनुसार रहता है। प्रारम्भिक अवस्था में भू—भाग वनस्पति आवरण से आच्छादित या वनस्पति विहीन रहता है। ऐसे किसी भू—भाग जो मानवीय प्रभाव से अछूता है अथवा उसका उपयोग प्राकृतिक रूप से हो रहा है के लिए भू—प्रयोग शब्द उचित जान पड़ता है। यदि किसी भू भाग पर मानवीय प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है तो उस भू—भाग के लिए भूमि उपयोग के साथ ही भूमि संसाधन इकाई बन जाती है। भूमि उपयोग, भूमि प्रयोग को शोषाणात्मक प्रक्रिया, जिसमें भूमि का व्यावहारिक उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि 'प्रयोग' तथा 'उपयोग' में सूक्ष्म अन्तर है। प्रयोग शब्द संरक्षण के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है। जबकि उपयोग शब्द व्यवहार सूचक है। जहाँ 'प्रयोग' शब्द एक क्षणिक प्रक्रिया के रूप में प्रकृति प्रदत्त संसाधन के प्रयोग को सूचित करता है वहीं 'उपयोग' शब्द एक विकासशील दीर्घकालीन प्रक्रिया को व्यक्त करता है। वुड (1972) के मतानुसार भूमि प्रयोग प्राकृतिक भू–दृश्य या वनस्पति आच्छादित भू–पटल के सन्दर्भ में ही नहीं वरन् मानवीय क्रिया–कलापों से उत्पन्न उपयोगी सुधारों के रूप में भी प्रयुक्त होना चाहिए।

वैनजेटी (1972) ने भूमि उपयोग को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के संयोग का प्रतिफल माना है।

भूमि संसाधन उपयोग शब्द का प्रयोग प्रायः भू–अर्थशास्त्रियों ने किया है जिसमें भूमि संसाधन इकाई का उपयोग इष्टतम उपयोगिता विद्धान्तों के अनुरूप किया जाता है। मानव प्रभाव से रहित या अविकसित क्षेत्र उपयोगिता की दृष्टि से महत्वहीन होता है। अतएव सांस्कृतिक भूगोल के क्षेत्र में भूमि–उपयोग एक क्रियाशील संकल्पना है । जब किसी क्षेत्र की भूमि का उपयोग उस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के अनुसार होता है, तब भूमि का उपयोग स्वछन्द रूप से नहीं होता है। अतएव ऐसे भूमि उपयोग के लिए 'भूमि संसाधन उपयोग' शब्द का प्रयोग अधिक उचित है। बारलो ने (1954) ने भूमि संसाधन उपयोग के औचित्य का समर्थन करते हुए इसे भूमि की समस्याओं एवं नियोजन संबंधी विवेचन का महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके मतानुसार भू– आर्थि क दृष्टिकोण से भूमि उपयोग का प्राथमिक सम्बन्ध उसकी स्थिति, अवस्था, प्रतिस्पर्द्धा, परिवलेन एवं सामंजस्य से है जिसका प्रादुर्भाव भूमि संसाधनों के उपयोग से होता है।

भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण :

भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ–साथ औद्योगिकरण ने लोगों के भोजन तथा विकास के बीच असांमजस्य उत्पन्न कर दिया जिससे भूमि उपयोग तथा दुरूपयोग की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है। व्यक्ति तथा भूमि के मध्य अनुपात को घटाना भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि एक ओर कुछ भागों में जनसंख्या का

संकेन्द्रण होता जा रहा था, जबकि बहुत व्यापक क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या का सकेन्द्रण था। ऐसी स्थिति में कृषि के लिये आर्थिक महत्व की भूमि प्राप्त करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने की समस्या उग्र हो गयी थी। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण समझी गयी। सर्वेक्षण कार्य के प्रथम चरण में विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाली उपलब्ध भूमि के शुद्ध अंकन तथा सर्वेक्षण कर चित्रण करने की भी जटिल समस्या थी। ग्रामीण भारत में 5.67 लाख गांवों को मानचित्र पर अंकित करना भी सहज कार्य नहीं था।

भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य ग्रेट ब्रिटेन में स्टाम्प द्वारा किये गये भूमि सर्वेक्षण से प्रेरित भारतीय भूगोलवेताओं द्वारा किया गया। 1938 में भारतीय विज्ञान काँग्रेस संगठन (ISCA) क अधिवेशन में स्टाम्प ने ओवरसीज प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, उन्होंने भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण प्रारम्भ करने की राय दी थी।

भारत में सर्वप्रथम प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण का प्रारम्भ चटर्जी (1941) द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना तथा हावड़ा जिलों में भूमि उपयोग सर्वेक्षण पूर्ववर्ती विद्वानों के लिये आदर्श बन गया। 1941 के पश्चात् देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों (अलीगढ़, पटना, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस) के भूगोल विभागों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किये तथा देश के प्रत्येक भाग में भूमि सर्वेक्षण प्रारम्भ किये। सम्पूर्ण भारत का सर्वेक्षण करने के लिये चटर्जी ने (1953, 1956, 1962) सेम्पल सर्वेक्षण करके प्राकृतिक दशाओं की भिन्नता तथा अनेक तथ्यों की शिथिलता को देखते हुए पूर्ण आधार पर सर्वेक्षण पर बल दिया। प्रकाशराव (1956) ने इस पर असहमति जताते हुए भूमि वर्गीकरण के मानचित्र तैयार करने की कार्याविधि बतायी। उन्होंने गोदावरी घाटी क्षेत्र में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण तथा अध्ययन किया। शफी (1951) ने भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर बल देते हुए भूमि के अधिकतम उपयोग तथा इसके लाभों का पता लगाने के लिये एक अभियान छेड़ा तथा वृहत पैमाने पर कार्य विधि तैयार की। शफी ने 1956 में उत्तरप्रदेश के 12 गाँवों का सर्वेक्षण किया जो उस समय में प्रथम प्रयास था। शफी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि (1960) इस दिशा में 'मील का पत्थर' सिद्ध हुआ। स्टाम्प ने भी शफी के कार्य की भरपूर प्रशंसा की। शफी ने 1966 ई0 में लन्दन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ (IGU) के 20वें अधिवेशन में सर्वेक्षण की निश्चित पद्धतियों को प्रस्तुत किया

तथा बताया कि ग्रामीण भूमि सर्वेक्षण न केवल भारत के लिये, अपितु अन्य देशो के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगा।

विगत वर्षों में अध्ययन की नयी सांख्याकीय तथा मात्रात्मक पद्धतियों के विकसित होने से सर्वेक्षण में नये आयाम जुड़ गये हैं। इनके आधार पर शफी (1964) के गंगा–जमुना दोआब क्षेत्र पर विस्तृत अध्ययन किया जो स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के क्षेत्र में गांगुली (1933) भारद्वाज (1961), उजागिर सिंह (1956), आर0एल0 सिंह (1951), विजयराम सिंह (1961), वी0के0 राय (1961), के0 जैड अमानी (1964), एस0एल0 कायस्थ (1964), एस0एन0 मिश्र (1964), हरिहर गिरि (1965), एम0एफ0 सिद्दीकी (1967), ए0 अहमद (1967), यूनिस रजा, प्रमला कुमार, रेड्ड, एस0एन0 मुखर्जी, एन0पी0 अययर (1968), जे0एन0 पाण्डेय, 1972), अली मुहम्मद, नूर मुहम्मद, बी0पी0 पण्डा, बी0पी0 सिंह, आर0पी0 मिश्र, माजिद हुसैन (1979) आदि के कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं। जसबीर सिंह (1974), द्वारा प्रकाशित भारत का कृषि एटलस तथ भारत का कृषि भूगोल (1979) इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पी0एस. तिवारी (1970) द्वारा प्रकाशित उत्तरप्रदेश का कृषि एटलस तथा एल0आर0 सिंह का कार्य सम्मिलित है। वर्तमान समय में भूमि उपयोग शोध एवं सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों के लिये UGC, ICSSR, ICAR सहित अनेक राष्ट्रीय संस्थान सक्रिय है तथा कृषि विकास हेतु प्रयासरत है।

विश्व के लगभग सभी देशों में भूमि उपयोग संबंधी कार्य किये जा रहे हैं। इस पद्धति से कृषि विकास में सफलता भी मिली है।

3. अनुसंधान की जाने वाली समस्या :–

जैसा कि वर्णित किया जा चुका है, सिमडेगा जिला का कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र से अधिक वनाच्छादित तथा बंजर भूमि क्षेत्र है। यहाँ की आबादी बहुतायत में निर्धन अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण है। यहाँ की कृषि भूमि उपयोग विकसित नहीं हो सका है, जबकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अतः सिमडेगा जिला में कृषि भूमि–उपयोग के बदलते स्वरूप से संबंधित शोध समस्याओं का अन्वेषण निम्नलिखित बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैः–

1) सिमडेगा जिला में कृषि भूमि उपयोग के बदलाव का क्या स्वरूप रहा है? अर्थात्

(क) कुल बोया गया क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी आयी है ?

(ख) वास्तविक बोये हुए क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

(ग) दुपज (दो फसली) क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है।

2) कृषि भूमि उपयोग के बदलाव के क्या–क्या कारण रहे हैं ?

3) सिमडेगा जिला में कृषि भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप से संबंधित समस्याओं के समाधान के क्या–क्या उपाय हो सकते हैं ?

4. अनुसंधान और प्रेरणा के स्रोत :–

हम प्रस्तुत शोध के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्य को लेकर चल रहे है–

1) जिला के प्राकृतिक स्वरूप के कारण कृषि भूमि उपयोग के स्वरूप में होने वाले बदलाव की पहचान करना है।

2) जिला का कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत समस्त बोया गया क्षेत्र तथा वास्तविक बोया गया क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की पहचान करना है।

3) नगरीकरण तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषित तथा कृषि योग्य भूमि में पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है।

4) चारागाह तथा नयी भूमि की पहचान कर कृषि योग्य भूमि के रूप में विस्तार करना है।

5) सिमडेगा जिला को कृषि में आत्मनिर्भर बनाकर लोगों में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि समस्याओं पर अंकुश लगाना है।

6) हमारे शोध कार्य से किसी भी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सिमडेगा जिला के कृषि भूमि उपयोग से संबंधित जाननकारियाँ प्रापत होगी वहीं भविष्य में विद्यार्थियों को भी हमारे शोध कार्य से लाभ प्राप्त होगा।

7) सिमडेगा के विकास के लिये नीतियाँ बनायी जाएगी उस समय हमारे द्वारा किये गये शोध तथा सुझावों का उपयोग किया जायेगा।

5. शोध परिकल्पना या अनुसंधान प्रश्न :–

– जिला का प्राकृतिक स्वरूप कृषि भूमि उपयोग को सीमित करता है। जिससे कृषि भूमि उपयोग के स्वरूप में संतोषजनक परिवर्तन संभव नहीं हो सका है।

– कृषि योग्य भूमि की अन्तर्गत समस्त बोया हुआ क्षेत्र तथा वास्तविक बोया गया क्षेत्र में कालिक परिवर्तन हुआ हैं

– जनसंख्या वृद्धि/जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि तथा बढ़ते हुए नगरीकरण के परिपेक्ष्य में कृषित एवं कृषि योग्य भूमि क्रमशः सिकुड़ रही है।

– चारागार तथा नयी भूमि को कृषित भूमि में बदलकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार सम्भव है।

6. अनुसंधान की रूपरेखा तथा पद्धति :–

यह शोध कृषि भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप का अध्ययन है। प्रस्तुत शोध में कृषि भूमि उपयो से संबंधित द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण होगा जो स्थानिक सर्वेक्षण से होगा। कृषि अनुसंधान के अन्तर्गत अवलोकन, प्रतिदर्शन और आंकलन होगा। शोध संरचना वर्णनात्मक होंगे, इसके साथ सांख्यिकी तालिकाएँ, मानचित्र एवं आरेखों, रेखा चित्रों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

6 A. संभावित अध्यायीकरण :–

शीर्षक– सिमडेगा जिला में कृषि भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप : भौगोलिक विश्लेषण।

परिचय

प्रथम अध्याय – भौगोलिक पृष्ठभूमि

द्वितीय अध्याय – भूमि उपयोग एवं कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप

तृतीय अध्याय – फसल प्रतिरूप

चतुर्थ अध्याय – प्रतिदर्श अध्ययन

पंचम अध्याय – कृषि– भूमि उपयोग का बदलता प्रतिरूप

षष्टम् अध्याय – कृषि भूमि उपयोग बदलते प्रतिरूप कारण एवं परिणाम

सप्तम् अध्याय – कृषि भूमि उपयोग की समस्याएँ तथा समाधान

अष्टम अध्याय – कृषि भूमि विकास के लिए नियोजन

निष्कर्ष

संदर्भ – ग्रंथ

परिशिष्ट

7. आँकड़ों के स्रोत तथा आँकड़ा संग्रहण में प्रयुक्त उपकरण :–

शोध से संबंधित अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित होगा। इन आंकड़ों की प्राप्ति निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये जा सकते हैं:–

1) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 1971 का भू–पत्रक1:50000 आकार का।

2) भारतीय मौसम विभाग तथा ISRO से जलवायु संबंधी मानचित्र तथा आंकड़े।

3) कृषि भूमि उपयोग से संबंधित G.I.S. की सहायता से प्राप्त उपग्रह मानचित्र तथा आंकड़े ISRO, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा भू–राजस्व विभाग से प्राप्त किया जाएगा।

4) जनांकिकीय आंकड़े तथा सामाजिक आर्थिक संबंधी आंकड़े भारत की जनगणना, जिला सांख्यिकीय पत्रिका से प्राप्त की जाएगी। इसके अलावे विभिन्न मंत्रालयों जैसे– कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, जन–कल्याण मंत्रालय आदि, विभिन्न पुस्तक, पत्र–पत्रिकाओं, सर्वे–रिपोर्ट, वेबसाइट आदि से भी आंकड़े एकत्रित किये जाएंगे।

5) वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिये इन्टरनेट तथा कम्प्यूटर की भी आवश्यकता होगी एवं फोटोग्राफी के लिये कैमरा का भी प्रयोग किया जाएगा।

8. आँकड़ों का विश्लेषण :–

द्वितीयक आंकड़ों में सबसे पहले 1971 का भू–पत्रक, उस क्षेत्र के अनेक प्रकार के मानचित्र जैसे – भारत, झारखण्ड, सिमडेगा जिला का भौतिक तथा राजनीतिक, भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र, जलवायु संबंधी मानचित्र आदि का विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाएगा।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी 1971 का 1:50,000 आकार का भू–पत्रक की प्राप्ति जिला मुख्यालय से किया जाएगा। इसके बाद उस क्षेत्र से संबंधित अनेक प्रकार के मानचित्र जैसे – जिला का भौतिक, राजनीतिक मानचित्र तथा कृषि भूमि उपयोग का G.I.S. के माध्यम से प्राप्त होने वाला उपग्रह मानचित्र, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, ISRO, भू–राजस्व विभाग आदि संगठनों से प्राप्त किया जाएगा। जनांकिकीय आंकड़े तथा सामाजिक–आर्थिक संबंधी आंकड़े, भारत की जनगणना, जिला सांख्यिकीय पत्रिका, भारत का योजना आयोग, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, कृषि मंत्रालय तथा जिला मुख्यालय के कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, वन विभाग आदि कार्यालयों से प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों से जैसे –NCERT सुचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पुस्तक भारत, जे0पी0 शर्मा की प्रायोगिक भूगोल, कृषि भूगोल से संबंधित पुस्तकें, वहीं पत्रिकाओं में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'योजना', ग्रामीण विकास मंत्रालय की 'कुरूक्षेत्र', भूगोल और आप, आदि पत्रिकाओं के अलावा समाचार–पत्र, सर्वे–रिपोर्ट तथा संबंधित वेबसाइट का भी उपयोग किया जाएगा।

9. अध्ययन का महत्त्व :–

सिमडेगा जिला वन सम्पदा से परिपूर्ण है, परंतु कृषि योग्य भूमि इसमें भी उपजाऊ भूमि नदी–घाटियों तक सीमित है जो कि यह प्रदेश पठारी भू–भाग, पर्ततों–घाटियों से भरा पड़ा है। इस प्रकार एक तरफ प्राकृतिक स्वरूप के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत ही सीमित है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जनता गरीबी से त्रस्त रहती है, क्योंकि मुख्यतः यहाँ एक फसलीय कृषि प्रणाली प्रचलित है। वर्ष का 8 महीना लगभग शुष्क रहता है एवं बिना सिंचाई के फसलों का उत्पादन सम्भव नहीं है जबकि यहाँ सिंचाई का विकास भी नहीं हो सका है। सिंचाई के विकास की चुनौती के साथ–साथ आबादी के बढ़ोतरी के कारण जल उपयोग की भी मात्रा काफी बढ़ गयी है, जिससे जल की अलग से समस्या उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में फसल

चक्र को संतुलित करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाना अनेक समस्याओं से बोझिल है।

सिमडेगा जिला एकल फसल उत्पादन प्रणाली और अविकसित कृषि पद्धति एवं कृषि के विकास के लिये सरकारी प्रयासों का नगण्य प्रभाव के कारण उत्पादन दर बहुत ही कम है, जिससे यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गरीबी, भूख, अर्द्धपोषण, कुपोषण, बेरोजगारी तथा पलायन आदि समस्याओं का दंश झेल रही है, जिसका एकमात्र निदान कृषि भूमि उपयोग को नियोजित कर उत्पादन में वृद्धि करना ही है, फलतः कृषि भूमि उपयोग को नई दिशा प्रदान करना ही एकमात्र विकास की राह है।

प्रस्तावित शोध इसी संदर्भ में अपना महत्व रखता है। यही भूमि उपयोग के कारकों का आंकलन करते हुए भूमि उपयोग को एक नवीनतम विकसित दिशा प्रदान करना है। इससे उत्पादन में वृद्धि सालो भर खेती की जा सकती है। इसी तरह यह शोध कृषकों, कृषि वैज्ञानिकों, सरकार, स्थानीय सरकार और योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अध्ययन से एक विकास की दिशा निर्दिष्ट होगी

10. वर्त्तमान समय की समस्या और समाज की आवश्यकता में इसकी प्रासंगिकता :—

सिमडेगा जिला में झारखण्ड के अन्य जिला की भांति कृषि के अनवरत प्रयास किये गये हैं। परंतु कृषि भूमि उपयोग में रूढ़िवादिता अभी भी विद्यमान है, सरकारी तंत्रों का प्रभाव बहुत ही सीमित रह गया है एवं अशिक्षा एवं अर्थाभाव का प्रभाव भी है, जिससे भी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि सम्भव नहीं हो पा रहा है। फलतः वर्तमान स्थिति में भूमि उपयोग संबंधी ऐसे शोध की आवश्यकता है ताकि यहाँ के ग्रामीण समाज को एक ऐसी दिशा मिल सके जिससे कृषि भूमि उपयोग विकसित कर लोगों को रोजगार प्रदान करें, भूख, पलायन, अर्द्धपोषण तथा कुपोषण से निजात दिलाएँ।

शोध द्वारा प्रस्तुत दिशा—निर्देश प्रासंगित इसलिए भी है, कि यह शोधस ऐसे दिशा निर्देशित करेगा जिससे कृषि विकास के सरकारी प्रयासों और कृषि विकास प्रसार सेवाओं की विफलताओं को समझकर कृषि उन्नति के लिए वैसे ही प्रभाव पैकेज प्रोग्राम को लागू करें।

11. वर्तमान ज्ञान में योगदान :—

वर्तमान ज्ञान सिमडेगा जिला के कृषि भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप का भौगोलिक अध्ययन के साथ—साथ शोध के अन्त में समस्याओं को पहचान तथा समाधान के लिए विकास की दिशा संकलित की जाएगी। इस प्रकार का विशिष्ट अध्ययन सिमडेगा जिला के लिए नया प्रयोग है। समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन करते हुए कृषि भूमि उपयोग का विस्तृत वितरण जिसके अन्तर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन, भूमि उपयोग वर्गीकरण, फसल प्रतिरूप/प्रारूप, जल संसाधन जो सिंचाई के लिए आवश्यक है और समस्याओं का संकलन इस जिला के लिए महत्वपूर्ण ज्ञानवर्द्धक का कार्य करेगी।

12. भविष्य के लिए कार्य :—

प्रस्तावित शोध भविष्य में अन्य प्रकार के शोध कार्य के लिए दिशा—निर्देश कर सकता है। कृषि भूमि उपयोग संबंधी अन्य प्रकार का अध्ययन के लिए जैसे — कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता, भूमि उपयोग, फसल संयोजन, फसल सघनता, कृषि ेत्र की नयी तकनिकी विकास, कृषि योजना इत्यादि अध्ययनों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। इसके अलावे इस प्रकार के शोध कार्य झारखण्ड के अन्य ऐसे ही भौगोलिक क्षेत्रों के लिए लागू हो सकते हैं।

13. संदर्भ सूची :

1. Stamp L.D. (1962) - The Land of Great Britian. Its used and misure, London, 1962.
2. Symon L. (1968) - Agricultural Geography.
3. Bansil D.C. (1978) - Agricultural Problems in India.
4. Mohammad A.(1978) - Studies in Agriculture Geography.
6. Bahagat L.N. (1981) - Adotion of New Agricultgural Practices in Tribal Bihar, The View from the Village.

7. शर्मा बी0एल0 (1988) – कृषि भूगोल, साहित्य भवन आगरा।

8. तिवारी आर0सी0 एवं सिंह बी0एन0 (1994), कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक

9. तिवारी राम कुमार (2002), झारखण्ड का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

10. ममोरिया चतुर्भुज एवं महतो भूपाल कुमार (2004), झारखण्ड का प्रादेशित भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

11. ममोरिया चतुर्भुत (2007), एग्रीकल्चरल प्रोब्लेम्स ऑफ इंडिया, किताब महल, इलाहाबाद।

12. हुसैन माजिद (2010), कृषि भूगोल, आत्मा राम एवं सन्स, दिल्ली।

13. गौतम अलका (2010), भारत का भूगोल, शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद।

14. गौतम अलका (2011), कृषि भूगोल, शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद।

15 सिंह गोपाल (2010), भारत का भूगोल, आत्मा राम एवं सन्स, दिल्ली।

16. पाण्डेय जे0एन0 एवं कमलेश एस0आर0 (2010), कृषि भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, दाउदपुर, गोरखपुर।

17. सिंह सुनील कुमार (2012), झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन बुक्स पब्लिकेशन्स, राँची।

18. रामकुमार तिवारी – झारखण्ड का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

19. श्याम कुमार – झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन सफल प्रकाशन, अपर बाजार, राँची।

20. NCERT – भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, NCERT कैम्पस श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।

21. योजना – योजना आयोग, 538 योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

22. http://simdega.nic in/glance html

23. http://census india.gov.in

24. http://simdega forest.nic.in

25. http://simdega nic in agri.html.